संख्या-730/2026/1241/22-2-2025-17(1209)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 11 जून, 2026

विषय:- जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पर्वत कुशवाहा पुत्र मुकुन्दी कुशवाहा, निवासी जनपद-दतिया (म0प्र0) की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-25779/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.06.2025), दिनांक 25.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पर्वत कुशवाहा पुत्र मुकुन्दी कुशवाहा, जो रिछरा फाटक, थाना-कोतवाली, जनपद-दतिया (म0प्र0) का निवासी है। पूर्व में हुयी हत्या में गवाही दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 20-08-2007 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर राजेश व शंकर नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-93/2008, भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01 झांसी के आदेश दिनांक 31.08.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। सत्र परीक्षण संख्या-686/2023 में भा0द0वि0 की धारा-392, 411 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (द०प्र०से०), झाँसी के आदेश दिनांक 20.12.2024 द्वारा 14 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचारधीन है। बंदी द्वारा प्रथम केस में दिनांक 16.03.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 14 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 09 माह, 03 दिन तथा द्वितीय केस में दिनांक 20.05.2025 तक अपरिहार 02 वर्ष 29 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष, 01 माह, 20 दिन की सजा पूरी कर ली है (द्वितीय केस में 14 वर्ष की अपरिहार सजा पूर्ण न होने के कारण फार्म-ए पर अपात्र)।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, भविष्य में अपराध किये जाने की प्रबल सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखा जाना समीचीन प्रतीत होने. पर बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में हुयी हत्या में गवाही दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनाक 20.08.2007 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर राजेश व शंकर नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एव जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एव जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बदी पर्वत कुशवाहा पुत्र श्री मुकुन्दी कुशवाहा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की सस्तुति नहीं की गई है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पर्वत कुशवाहा (बन्दी संख्या-940/10) पुत्र श्री मुकुन्दी कुशवाहा, निवासी जनपद-दतिया (म0प्र0) की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-730/2026/1241(1)/22-2-2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झांसी।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, झांसी।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-730/2026/1241/22-2-2025-17(1209)/2023

दिनांकः 11 जून, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पर्वत कुशवाहा पुत्र मुकुन्दी कुशवाहा, जो रिछरा फाटक, थाना-कोतवाली, जनपद-दतिया (म0प्र0) का निवासी है। पूर्व में हुयी हत्या में गवाही दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 20-08-2007 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर राजेश व शंकर नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-93/2008, भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01 झांसी के आदेश दिनांक 31.08.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। सत्र परीक्षण संख्या-686/2023 में भा0द0वि0 की धारा-392, 411 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (द०प्र०से०), झाँसी के आदेश दिनांक 20.12.2024 द्वारा 14 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचारधीन है। बंदी द्वारा प्रथम केस में दिनांक 16.03.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 14 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 09 माह, 03 दिन तथा द्वितीय केस में दिनांक 20.05.2025 तक अपरिहार 02 वर्ष 29 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष, 01 माह, 20 दिन की सजा पूरी कर ली है (द्वितीय केस में 14 वर्ष की अपरिहार सजा पूर्ण न होने के कारण फार्म-ए पर अपात्र)।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, भविष्य में अपराध किये जाने की प्रबल सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखा जाना समीचीन प्रतीत होने. पर बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में हुयी हत्या में गवाही दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनाक 20.08.2007 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर राजेश व शंकर नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एव जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एव जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बदी पर्वत कुशवाहा पुत्र श्री मुकुन्दी कुशवाहा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की सस्तुति नहीं की गई है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in